

# एनएसएआई समाचार

## गवर्निंग काउंसिल

### प्रेसिडेंट

- डॉ एम प्रभाकर राव

### वाइस प्रेसिडेंट

- श्री दिनेशभाई बी पटेल

### जनरल सेक्रेटरी

- डॉ जय सिंह

### ट्रेजर

- श्री वैभव आर काशीकर

## मैम्बर्स

- श्री. च. रामबाबू
- श्री. के. प्रवीण कुमार
- श्री. सिद्धार्थ एस सेन
- श्री. अजीत मुले
- डॉ. गुंडावरम पवन
- श्री. पवन क्र. कंसल
- श्री. यू सरवनन
- श्री. एम रवि कुमार
- श्री. आर. डी. पटेल
- डॉ. बी.बी. पटनायक
- डॉ. कीर्तन वाई पटेल

## एनएसएआई सेक्रेटेरिएट

- डॉ. आर.के. त्रिपाठी
- श्री. यशपाल सैनी
- डॉ. दीपांकर पांडे
- डॉ. प्रमोद शर्मा
- डॉ. आशिमा बठेजा
- सुश्री. सेलेस्टे वर्गीस

भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) ने नई दिल्ली में "कॉटन 2040: प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धात्मकता" विषय पर चौथा वैश्विक कपास सम्मेलन आयोजित किया।

एनएसएआई के निदेशक (तकनीकी) डॉ. आर. के. त्रिपाठी और उप निदेशक (तकनीकी) डॉ. दीपांकर पांडे ने मंगलवार, 7 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में "कॉटन 2040: प्रौद्योगिकी, जलवायु और प्रतिस्पर्धात्मकता" विषय पर आयोजित चौथे वैश्विक कपास सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (CITI) द्वारा केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और भारतीय कपास निगम के सहयोग से विश्व कपास दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ (NSAI) ने एक भागीदार संघ के रूप में भाग लिया, जबकि भारतीय खाद्य एवं कृषि चैंबर (ICFA) ने इस आयोजन के लिए ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य किया।

सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (TEXPROCIL) और CITI-CDRA का समर्थन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिता ने किया और केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मुख्य अतिथि भाषण दिया।

बायर के श्री राजवीर राठी सहित कई उद्योग जगत के नेताओं ने सत्रों के दौरान अपने विचार साझा किए। पैनलिस्टों ने किसानों, उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए जीत-जीत का ढांचा बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करना और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को मजबूत करना भारत के सूती वस्त्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्रम का समापन CITI के उपाध्यक्ष श्री दिनेश नोलखा द्वारा दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।



## एफएसएसएआई (FSSAI) ने एफडीए भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 48वीं बैठक का आयोजन

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 14 अक्टूबर, 2025 को एफडीए भवन, नई दिल्ली में अपनी केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की 48वीं बैठक आयोजित की। यह बैठक एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में आयोजित की गई और इसमें सीएसी के नव मनोनीत सदस्य, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त, एफएसएसएआई वैज्ञानिक समिति के सदस्य और एफएसएसएआई के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ (NSAI) के निदेशक (तकनीकी) डॉ. आर. के. त्रिपाठी ने केंद्रीय सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्य के रूप में बैठक में भाग लिया। परिचयात्मक सत्र के दौरान, डॉ. त्रिपाठी ने अपनी व्यावसायिक पृष्ठभूमि और तकनीकी विशेषज्ञता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कृषि विज्ञान, बीज प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा नियमों के क्षेत्र में अपने व्यापक अनुभव के बारे में विस्तार से बताया। डॉ. त्रिपाठी ने उन संभावित क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला जहाँ वे भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने में योगदान दे सकते हैं, विशेष रूप से ट्रेसिबिलिटी को बढ़ावा देने, खाद्य मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने और बीज एवं खाद्य क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने में। उन्होंने वैज्ञानिक और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोणों के माध्यम से जन स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य प्रणालियों की अखंडता में सुधार लाने के उद्देश्य से FSSAI की पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

यह बैठक सदस्यों के लिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रमुख नीतिगत और नियामक मामलों पर विचार-विमर्श करने, उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने और देश भर में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहयोगात्मक रणनीतियों का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।



### **साथी पोर्टल पर प्रजनक बीज मांगपत्र संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु बैठक आयोजित**

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर आयुक्त (बीज) श्री आनंद कुमार प्रभाकर की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2025 को कृषि भवन, नई दिल्ली में साथी पोर्टल के माध्यम से रबी फसलों के लिए प्रजनक बीज मांगपत्र प्रस्तुत करने और उसे अंतिम रूप देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई।

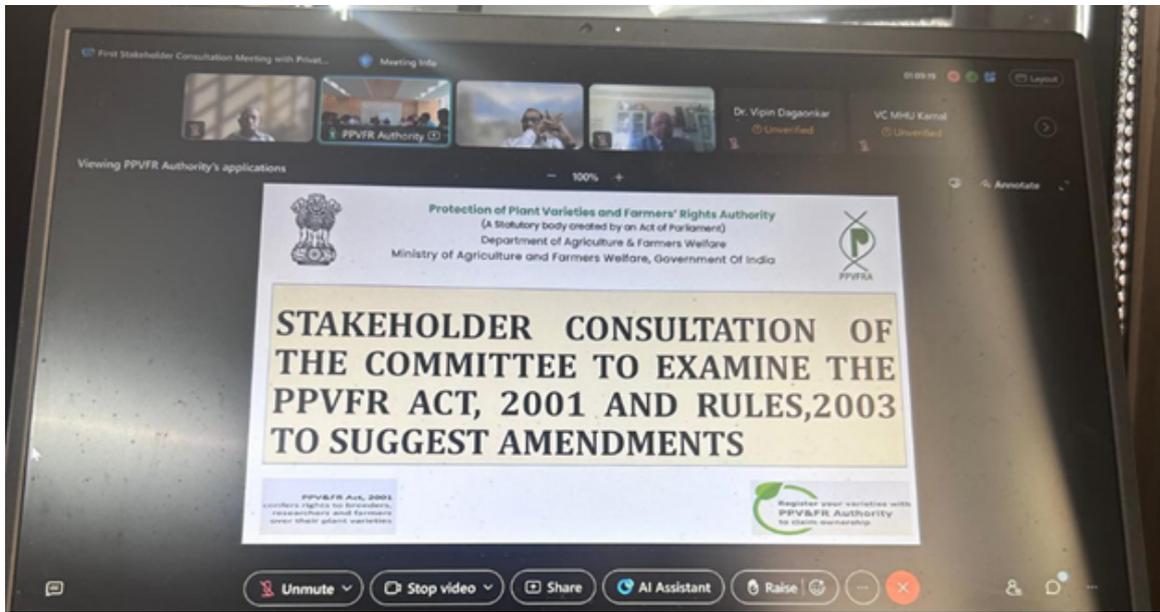
बैठक में बीज प्रभाग के अधिकारियों, राज्य कृषि विभागों के प्रतिनिधियों, भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ (NSAI) और साथी प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करने वाली तकनीकी टीम ने भाग लिया। एनएसएआई से सहायक निदेशक, डॉ. प्रमोद शर्मा और अनुसंधान सहयोगी, डॉ.आशिमा बठेजा ने बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान, पोर्टल की कार्यक्षमता और डेटा सटीकता के संबंध में कई प्रमुख चिंताएँ व्यक्त की गईं। बताया गया कि मध्य प्रदेश की प्रजनक बीज मांगपत्र रिपोर्ट में निजी बीज कंपनियों के डेटा शामिल थे, जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। एनएसएआई ने दो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान दिलाया, कुछ गैर-सदस्य कंपनियों के प्रजनक बीज मांगपत्रों का दिखाई देना और उसकी छह सदस्य बीज कंपनियों के मांगपत्रों का न होना। अध्यक्ष ने संबंधित एजेंसियों को एनएसएआई के साथ समन्वय करके इन विसंगतियों का समाधान करने का निर्देश दिया। प्रतिभागियों ने यह भी बताया कि बीज उत्पादक एजेंसियों (एसपीए) और मांगकर्ताओं के लॉगिन क्रेडेंशियल ठीक से काम नहीं कर रहे थे, और साथी पोर्टल पर बीज प्रभाग के लॉगिन के अंतर्गत तिलहन और दलहन फसलों की रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रही थी। इसके अतिरिक्त, प्रजनक बीज आवंटन की कार्यक्षमता में भी खराबी पाई गई, जिससे आवंटन प्रक्रिया में देरी हो रही थी। अध्यक्ष ने तकनीकी टीम को पोर्टल के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का निर्देश दिया।

चर्चा का एक अन्य बिंदु वर्तमान रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रजनक बीज मांग रिपोर्ट के प्रारूपों को अद्यतन करने की आवश्यकता थी। बीज प्रभाग और साथी तकनीकी टीम को अगले मांग चक्र से पहले संशोधित टेम्पलेट्स को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया। श्री प्रभाकर ने आगामी रबी सीजन के लिए प्रजनक बीज के सुचारू नियोजन की सुविधा के लिए डेटा अखंडता, प्रणाली दक्षता और सभी तकनीकी मुद्दों के समय पर समाधान के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सुधारात्मक कार्रवाई की प्रगति का आकलन करने तथा प्रजनक बीज प्रबंधन के लिए SATHI पोर्टल की पूर्ण कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए तीन सप्ताह के भीतर अनुवर्ती समीक्षा आयोजित करने के निर्णय के साथ समापन हुआ।

## पीपीवीएफआर (PPVFR) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा हेतु पहली हितधारक परामर्श बैठक आयोजित

पौधा किस्मों एवं कृषकों के अधिकार संरक्षण (पीपीवीएफआर) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा हेतु 25 अक्टूबर, 2025 को प्रातः 10:30 बजे डॉ. आर. एस. परोदा की अध्यक्षता में एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एनएसएआई सचिवालय के निदेशक (तकनीकी) डॉ. आर. के. त्रिपाठी और उप निदेशक डॉ. दीपांकर पांडे के साथ-साथ भारतीय बीज उद्योग के कई प्रमुख लोग शामिल हुए।



प्रतिभागियों ने प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया और उन प्रमुख प्रावधानों की पहचान की जिनमें बीज क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहुमूल्य सुझाव और अंतर्दृष्टि साझा की कि संशोधन नवाचार, किसानों के अधिकारों और भारतीय बीज उद्योग के सतत विकास का समर्थन करने वाला एक संतुलित ढाँचा बनाए रखें।

बैठक का समापन डॉ. परोदा द्वारा प्रतिभागियों के रचनात्मक योगदान की सराहना करने तथा चल रही पीपीवीएफआर संशोधन प्रक्रिया में बीज उद्योग की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए निरंतर सहयोग के महत्व को रेखांकित करने के साथ हुआ।

## पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण द्वारा एमएलटीएस (MLTS) आईटीपीजीआरएफए (ITPGRFA) में अनुलग्नक 1 फसलों के संबंध में किसानों की परामर्श बैठक आयोजित

27 अक्टूबर, 2025 को, पीपीवी एंड एफआर प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली स्थित प्लांट अथॉरिटी भवन में एमएलटीएस आईटीपीजीआरएफए में अनुलग्नक 1 फसलों के संबंध में किसानों के परामर्श हेतु एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पीपीवी एंड एफआरए के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने की और इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बीज) श्री अजीत कुमार साहू; आईसीएआर के उपमहानिदेशक (फसल विज्ञान) डॉ. डी. के. यादव; श्री विलास डी. सोनवणे; एनबीपीजीआर के निदेशक डॉ. जी. पी. सिंह; और उपायुक्त (बीज) श्री एम. गुनाशेखरन सहित कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक में सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, निजी बीज कंपनियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ (एनएसएआई) की ओर से निदेशक (तकनीकी) डॉ. आर. के. त्रिपाठी और सहायक निदेशक (तकनीकी) डॉ. प्रमोद शर्मा ने बैठक में भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से आईटीपीजीआरएफए की जीबी की 11वीं बैठक के अनंतिम एजेंडे के प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे कि आईटीपीजीआरएफए के तहत सभी पीजीआरएफए में फसलों का विस्तार, जिसमें वर्तमान में 35 खाद्य और 29 चारा फसलें शामिल हैं, साथ ही निष्पक्ष और न्यायसंगत लाभ साझाकरण और डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) प्रणाली से संबंधित मामले।





चर्चा के दौरान, इस बात पर जोर दिया गया कि भारत को सोयाबीन, मूंगफली, टमाटर और तरबूज जैसी प्रमुख फसलों तक पहुंच प्राप्त करनी चाहिए, जो वर्तमान में भारतीय प्रजनकों का समर्थन करने के लिए अनुलग्नक 1 फसल सूची में शामिल नहीं हैं। यह प्रस्ताव रखा गया कि खाद्य सुरक्षा, प्रजनन कार्यक्रमों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त फसलों को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अनुलग्नक 1 सूची में शामिल किया जाना चाहिए। प्रतिभागियों ने चिंता व्यक्त की कि लाभ-साझाकरण निधि में वर्तमान मौद्रिक योगदान अपर्याप्त है; दिशानिर्देश लाभ-साझाकरण निधि जारी करने का स्पष्ट आदेश नहीं देते हैं, इसलिए, एक अधिक प्रभावी और पारदर्शी ढाँचा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अग्रिम भुगतान वाली एक प्रस्तावित सदस्यता-आधारित प्रणाली का सुझाव दिया गया।

यह भी सुझाव दिया गया कि डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) को बहुपक्षीय प्रणाली के साझाकरण ढाँचे में एकीकृत किया जा सकता है। डीएसआई के उपयोग से अनुसंधान और प्रजनन उद्देश्यों के लिए आनुवंशिक डेटा तक आसान और व्यापक पहुँच संभव होगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि लाभ-साझाकरण सिद्धांत भौतिक जर्मप्लाज्म और डिजिटल आनुवंशिक अनुक्रम सूचना, दोनों पर लागू हों। यह भी सुझाव दिया गया कि एमएलएस के तहत पहुँच और लाभ-साझाकरण तंत्र का व्यावहारिक रूप से परीक्षण और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने अभी तक इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी सामग्री साझा नहीं की है। इससे ढाँचे की प्रभावशीलता का आकलन करने और बहुपक्षीय प्रणाली में भारत की भागीदारी को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।

संयुक्त सचिव (बीज) श्री अजीत कुमार साहू ने महसूस किया कि मौजूदा बहुपक्षीय प्रणाली (एमएलएस) में कई कमियाँ हैं और जर्मप्लाज्म विनिमय के लिए अनधिकृत या अवैध माध्यमों के उपयोग को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रभावी शासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक संरचित, पारदर्शी और कानूनी रूप से प्रवर्तनीय तंत्र स्थापित करके संधि के कार्यान्वयन को मजबूत करने की सिफारिश की।

अंत में, डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने संधि के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने, भारत के समृद्ध आनुवंशिक संसाधनों की रक्षा करने और अनुक्रम डेटाबेस की घोषणा और प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाने के लिए एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

## **एपीएसए (APSA) ने एशिया- पसिफ़िक क्षेत्र के बीज संघों के साथ ऑनलाइन बैठक का आयोजन**

एशिया और पसिफ़िक बीज गठबंधन (APSA ) ने 28 अक्टूबर 2025 को एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम सहित विभिन्न देशों के सदस्य बीज संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी मतदान प्रतिनिधियों, अधिकारियों और सचिवालय सदस्यों के लिए खुली इस बैठक की अध्यक्षता एपीएसए की कार्यकारी निदेशक सुश्री फ्रांसिन सायोक ने की, जिन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत किया और नियामक वकालत, सदस्य सहभागिता और परिचालन उत्कृष्टता पर केंद्रित APSA के रणनीतिक रोडमैप 2025-2027 के प्रथम वर्ष के कार्यान्वयन पर अद्यतन जानकारी प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ (एनएसएआई) का प्रतिनिधित्व महासचिव डॉ. जय सिंह और निदेशक (तकनीकी) डॉ. आर. के. त्रिपाठी ने किया।

APSA के तकनीकी सलाहकार, श्री शिवेंद्र बजाज ने 2025 में शुरू की गई प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें फाइटोसैनिटरी नियमों, पादप प्रजनन नवाचार, और पीवीपी एवं जैव विविधता पर परामर्श के साथ-साथ यूएसडीए और एएसटीए के सहयोग से आयोजित कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि APSA के अब 523 सक्रिय सदस्य हैं, इस वर्ष 71 नए सदस्य जुड़े हैं, और भारत सबसे अधिक सदस्य कंपनियों (139) के साथ अग्रणी है। श्री बजाज ने पेशेवर प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाने के लिए APSA बीज अकादमी का एएसएफ बीज उद्योग व्यावसायिक कार्यक्रम (SIPP ) के साथ विलय की भी घोषणा की।

APSA कार्यक्रम प्रबंधक, श्री माइक किंगपायोम ने 17-21 नवंबर को पुणे, भारत में होने वाले आगामी एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का विवरण प्रस्तुत किया, चर्चा के दौरान, हांगकांग बीज व्यापार संघ के डॉ. एंथनी त्से ने चीनी प्रतिनिधियों के वीज़ा में देरी पर चिंता जताई, जिस पर डॉ. जय सिंह ने आश्वासन दिया कि एनएसएआई मंजूरी की सुविधा के लिए भारत के विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है। बैठक का समापन करते हुए, तुर्कटेड के श्री केनान यालवैक ने प्रतिभागियों को 1-5 दिसंबर 2026 तक तुर्की के अंताल्या में आयोजित होने वाले एशियाई बीज सम्मेलन 2026 में आमंत्रित किया।



### **एनएसएआई और अर्जेटीना दूतावास ने अध्ययन यात्रा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए सहयोग किया**

अर्जेटीना दूतावास ने भारतीय बीज उद्योग प्रतिनिधिमंडल की आगामी अध्ययन यात्रा की योजना को अंतिम रूप देने के लिए 29 अक्टूबर, 2025 को भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ (एनएसएआई) के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। एनएसएआई टीम में श्री वैभव आर. काशीकर, श्री राम बाबू, डॉ. आर.के. त्रिपाठी (निदेशक, तकनीकी), डॉ. दीपांकर पांडे (उप निदेशक, तकनीकी), डॉ. प्रमोद शर्मा (सहायक निदेशक), और डॉ. आशिमा बठेजा (अनुसंधान सहयोगी) शामिल थे। श्री मारियानो बेहराम, मंत्री अताशे (कृषि), ने अर्जेटीना दूतावास का प्रतिनिधित्व किया।

शुरुआत में 13-17 अक्टूबर, 2025 के लिए निर्धारित यह यात्रा भारत में त्योहारों के मौसम के कारण स्थगित कर दी गई थी। बैठक के दौरान, एनएसएआई ने इस यात्रा को जनवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च 2026 में पुनर्निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। श्री बेहराम ने बताया कि मार्च, सोयाबीन और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की कटाई के समय से मेल खाता है, जबकि जनवरी के अंत में प्रतिनिधियों को ज्वार, सूरजमुखी, सोयाबीन और मक्का के खेतों का दौरा करने का अवसर मिलेगा। हालाँकि, उन्होंने यह भी बताया कि जनवरी अर्जेंटीना में छुट्टियों का मौसम भी होता है, इसलिए शीघ्र योजना और समन्वय की आवश्यकता है।

चर्चा के बाद, दोनों पक्ष जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में यात्रा निर्धारित करने पर सहमत हुए। श्री काशीकर ने प्रस्तावित कार्यक्रम को एनएसएआई सदस्यों के बीच प्रसारित करने और दस दिनों के भीतर उनकी पुष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री बेहराम ने तीन महीने के लिए वैध मार्केट स्टडी रिसर्च वीज़ा की उपलब्धता पर भी प्रकाश डाला, जिससे दौरे के आयोजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि चूँकि भारतीय बीज उद्योग महासंघ (FSII) इस अध्ययन दौरे में शामिल होने के लिए इच्छुक है, इसलिए NSAI को FSII की सहमति लेनी चाहिए और तदनुसार उनके साथ समन्वय करना चाहिए।

बैठक सकारात्मक रूप से संपन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने तथा भारतीय और अर्जेंटीना के बीज क्षेत्रों के बीच उत्पादक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

## बीज उद्योग अपडेट

**मंत्रिमंडल ने दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए ₹11,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी, रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया**

कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 01, 2025 को देश भर में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹11,000 करोड़ के छह-वर्षीय मिशन को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य दलहन आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना, घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हेतु ₹84,200 करोड़ को भी मंजूरी दी, जिससे किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और पुष्ट हुई।

दलहनों के लिए व्यापक योजना उच्च उपज देने वाली, कीट- और जलवायु-रोधी किस्मों के विकास पर केंद्रित है, जिसे क्षेत्रीय अनुकूलनशीलता सुनिश्चित करने के लिए बहु-स्थान परीक्षणों द्वारा समर्थित किया जाएगा। राज्य पंचवर्षीय चल बीज उत्पादन योजनाएँ तैयार करेंगे, जबकि प्रजनक बीजों का प्रबंधन ICAR द्वारा किया जाएगा और आधारभूत एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन और ट्रेकिंग SATHI पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। 2030-31 तक, 370 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जाने की उम्मीद है। मिशन का लक्ष्य अतिरिक्त 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती करना भी है, विशेष रूप से चावल की परती और उपयुक्त भूमि में। 88 लाख से अधिक बीज किट निःशुल्क वितरित किए जाएँगे, और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देंगे। मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए, 1,000 कटाई-पश्चात प्रसंस्करण इकाइयों को प्रत्येक को ₹25 लाख तक की सब्सिडी के साथ समर्थन दिया जाएगा। मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों की खरीद अगले चार वर्षों तक NAFED और NCCF द्वारा की जाएगी। इस योजना में किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक वैश्विक मूल्य निगरानी तंत्र भी शामिल है। इस मिशन के अंत तक, दालों का उत्पादन 350 लाख टन तक पहुँचने का अनुमान है, जो 310 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा और प्रति हेक्टेयर औसत उपज 1,130 किलोग्राम होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और कृषि लचीलापन बढ़ेगा।

## महाराष्ट्र में प्याज की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने से किसान फसलें फेंकने को मजबूर

महाराष्ट्र के प्याज क्षेत्र में एक गहरा कृषि संकट उभर रहा है, क्योंकि किसान बेमौसम बारिश और कीमतों में गिरावट की दोहरी मार झेल रहे हैं। पुणे जिले के पुरंदर में, किसान सुदाम इंगले ने हाल ही में 7.5 क्विंटल प्याज केवल ₹664 में बेचा, जिससे परिवहन और तौल शुल्क घटाने के बाद उन्हें प्रति किलोग्राम ₹1 से भी कम की कमाई हुई। महीनों की कड़ी मेहनत और बढ़ती खेती की लागत के बाद मिलने वाले मामूली मुनाफे ने किसानों को तबाह कर दिया है। नासिक के एक निराश कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) सदस्य ने कहा, "इस साल दिवाली केवल शहरों में मनाई जा रही है। गाँवों में तो दीया खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं।" एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव एपीएमसी में थोक कीमतें ₹500 और ₹1,400 प्रति क्विंटल के बीच स्थिर हो गई हैं, औसतन लगभग ₹1,050, जो ₹1,800-₹2,000 से काफी कम है, किसानों का कहना है कि उन्हें केवल खर्चों को पूरा करने की जरूरत है। इस साल की शुरुआत में बंपर रबी (ग्रीष्म) की फसल, खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली भारी बारिश के साथ, खराब गुणवत्ता वाले प्याज की भरमार हो गई है जिसे न तो व्यापारी और न ही निर्यातक खरीदने के इच्छुक हैं। लाभकारी मूल्य न मिलने और उच्च परिवहन लागत के कारण, कई किसानों ने आगे के नुकसान को कम करने के लिए अपनी उपज को डंप करने या नष्ट करने का सहारा लिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट भारत की प्याज अर्थव्यवस्था में लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं, मूल्य अस्थिरता, अपर्याप्त भंडारण और नीति अनिश्चितता को रेखांकित करता है इस बीच, खुदरा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बार-बार लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों और स्टॉक सीमाओं ने किसानों का विश्वास कम किया है और इस क्षेत्र में निजी निवेश को हतोत्साहित किया है।

किसान संघ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद और मूल्य संवर्धन तथा आय स्थिरीकरण के लिए स्थानीय निर्जलीकरण और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने बफर स्टॉक खरीद बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) के माध्यम से केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। हालाँकि, फिलहाल ग्रामीण महाराष्ट्र में माहौल निराशाजनक बना हुआ है। जैसे ही शहर दिवाली की रोशनी से जगमगाते हैं, राज्य के प्याज उत्पादक क्षेत्र अंधेरे में डूब जाते हैं और उनके खेत समृद्धि से नहीं, बल्कि सड़ते हुए प्याज के ढेरों से भर जाते हैं, जो टूटी हुई उम्मीदों का प्रतीक हैं।

## आयात लागत की भरपाई के लिए सरकार ने गैर-यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गैर-यूरिया उर्वरकों, मुख्य रूप से फास्फोरस (P) और सल्फर (S) पर सब्सिडी में वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिससे 2025-26 रबी सीजन के लिए कुल परिव्यय बढ़कर ₹37,952 करोड़ हो गया। बढ़ती आयात लागत की भरपाई और किसानों के लिए उर्वरक की कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से की गई यह बढ़ोतरी अक्टूबर 01, 2025 से मार्च 31, 2026 तक प्रभावी रहेगी। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना के तहत, फास्फोरस के लिए सब्सिडी ₹43.60 प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर ₹47.96 प्रति किलोग्राम कर दी गई है, जबकि सल्फर की दर ₹2.61 प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹2.87 प्रति किलोग्राम हो गई है, जो खरीफ सीजन की तुलना में लगभग 10% अधिक है। नाइट्रोजन और पोटाश के लिए सब्सिडी दरें अपरिवर्तित रहेंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पैकेज पिछली रबी के ₹24,000 करोड़ के आवंटन से लगभग ₹14,000 करोड़ अधिक है। यह कदम फॉस्फोरिक एसिड, सल्फर और डीएपी की वैश्विक कीमतों में भारी वृद्धि के बाद उठाया गया है, और इससे खुदरा कीमतों में किसी भी वृद्धि के बिना किसानों को डीएपी और टीएसपी जैसे प्रमुख उर्वरकों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।



## **प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए सामूहिक खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का आग्रह किया**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर, 2025 को सामूहिक खेती की पहल का आह्वान किया और छोटे और सीमांत किसानों से उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और आय बढ़ाने के लिए भूमि साझा करने और उच्च मूल्य वाली फसलों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में बोलते हुए, मोदी ने ₹35,440 करोड़ के संयुक्त परिव्यय वाली दो प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (₹24,000 करोड़) और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (₹11,440 करोड़) का शुभारंभ करने से पहले देश भर के किसानों के साथ बातचीत की। उन्होंने विश्वास बढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ-साथ प्राकृतिक खेती को चरणबद्ध तरीके से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और मिट्टी की उर्वरता और अधिक उपज के लिए दलहन के साथ अंतर-फसल के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान, किसानों ने सफलता की कहानियाँ साझा कीं, जिनमें अवशेष-मुक्त काबुली चना की खेती, एरोपोनिक आलू की खेती, एकीकृत जैविक खेती और स्वयं सहायता समूहों के तहत डेयरी पहल शामिल हैं। उन्होंने सहकारी मॉडलों और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लाभों को दर्शाया। मोदी ने जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में बाजरे के संवर्धन, जलीय कृषि की संभावनाओं और गिर गाय समुदाय श्रृंखला जैसी स्थायी प्रथाओं पर भी ज़ोर दिया और आधुनिक कृषि में युवाओं की भागीदारी और उद्यमिता का आह्वान किया।

## **आईसीएल ने बायोप्राइम के साथ साझेदारी कर भारत में अगली पीढ़ी के जैव उर्वरक लॉन्च किए, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया**

वैश्विक फसल पोषण अग्रणी इज़राइल केमिकल्स लिमिटेड (ICL) ने भारत में उन्नत मृदा और फसल स्वास्थ्य समाधान पेश करने के लिए पुणे स्थित कृषि-जैविक नवप्रवर्तक बायोप्राइम के साथ एक रणनीतिक दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। यह सहयोग आईसीएल के माइक्रोबियल जैव उर्वरक क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है, जो बायोप्राइम के स्वामित्व वाले बायोनेक्सस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर अगली पीढ़ी के जैव उर्वरकों का व्यावसायीकरण करेगा, जिसका उद्देश्य पोषक तत्व उपयोग दक्षता (NUE) में सुधार करना है, विशेष रूप से फॉस्फोरस (P) और जिंक (Zn), जो भारतीय किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं।

यह साझेदारी किसानों को पोषक तत्वों के अवशोषण को अनुकूलित करने, उत्पादकता बढ़ाने और उर्वरक की बर्बादी को कम करने के साथ-साथ स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगी।

बायोप्राइम की सह-संस्थापक और सीईओ रेणुका करंदीकर ने कहा कि यह गठजोड़ आईसीएल के पैमाने और विशेषज्ञता द्वारा संचालित माइक्रोबियल नवाचारों को प्रयोगशाला से भूमि तक लाने में एक मील का पत्थर है। आईसीएल ग्रोइंग सॉल्यूशंस इंडिया के कंट्री लीड, अनंत कुलकर्णी ने कहा कि यह सहयोग टिकाऊ कृषि और नवाचार-आधारित विकास के प्रति आईसीएल की प्रतिबद्धता को और पुष्ट करता है। उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि यह गठबंधन जैव-उर्वरक क्षेत्र में दोनों कंपनियों की वृद्धि को 10-20 गुना बढ़ा सकता है, साथ ही भारत को उर्वरक आयात पर अंकुश लगाने और सब्सिडी के बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। भारत का जैव-उर्वरक बाजार 11.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है, और आईसीएल-बायोप्राइम साझेदारी को हरित, अधिक लचीली और लागत-कुशल खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

## **कॉर्टेवा ने अंगूर और आलू को फफूंद के खतरों से बचाने के लिए अगली पीढ़ी का कवकनाशी लॉन्च किया**

कॉर्टेवा एग्रीसाइंस ने भारत में अपने नवीनतम कवकनाशी, ज़ोरवेक एंटेक्टा के लॉन्च की घोषणा की है। यह कवकनाशी अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू और आलू में लेट ब्लाइट से निपटने में किसानों की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाले दो सबसे विनाशकारी कवक रोग हैं। कॉर्टेवा की स्वामित्व वाली ज़ोरवेक सक्रिय तकनीक द्वारा संचालित, यह नया समाधान प्रणालीगत, दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है, यहाँ तक कि नए पौधों की वृद्धि की भी रक्षा करता है और उपयोग के कुछ ही घंटों के भीतर उच्च वर्षा-प्रतिरोधकता प्रदान करता है। कंपनी प्रतिरोध प्रबंधन को मजबूत करने और व्यापक रोग नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपने मौजूदा कवकनाशी कर्ज़ेंट M8 के साथ ज़ोरवेक एंटेक्टा के उपयोग की अनुशंसा करती है। इस लॉन्च के साथ, कॉर्टेवा का लक्ष्य भारतीय उत्पादकों को नवीन, विज्ञान-संचालित उपकरणों से लैस करना है जो फसल के लचीलेपन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, और भारत के कृषि क्षेत्र में स्थायी और उन्नत फसल सुरक्षा समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।



## शिवराज सिंह चौहान ने उन्नत एनएससी बीज प्रसंस्करण इकाइयों का उद्घाटन किया और डिजिटल बीज प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली के पूसा कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) की अत्याधुनिक सब्जी और पुष्प बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने बरेली, धारवाड़, हासन, सूरतगढ़ और रायचूर में स्थित पाँच एनएससी बीज प्रसंस्करण संयंत्रों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भारत के बीज उत्पादन और वितरण नेटवर्क को मज़बूत करना है।

पूसा में नव स्थापित बीज भवन संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता एक टन प्रति घंटा है, जबकि अन्य पाँच संयंत्र चार टन प्रति घंटा प्रसंस्करण कर सकते हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस, इन सुविधाओं से देश भर के किसानों के लिए प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता और उपलब्धता में वृद्धि होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने 'बीज प्रबंधन 2.0' और एक ऑनलाइन बीज बुकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जिससे किसान डिजिटल रूप से बीज ऑर्डर कर सकेंगे। चौहान ने कहा कि यह पहल बीज वितरण को और अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाएगी, जिससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा।

'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के दौरान उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, चौहान ने कहा कि किसानों की कई शिकायतें नकली या निम्न-गुणवत्ता वाले बीजों से संबंधित थीं, और आश्वासन दिया कि सरकार ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, "ये नई सुविधाएँ किसानों की ज़रूरतों को पूरा करेंगी और कृषि

उत्पादकता में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाएँगी।" मंत्री ने एनएससी से नवाचार को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय भाषाओं में पहुँच बढ़ाने और राज्य बीज विकास निगमों के साथ समन्वय में सुधार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, "एनएससी जैसी सार्वजनिक संस्थाओं की एक विशेष ज़िम्मेदारी होती है। उन्हें किसानों की सेवा के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और एक मिशन के साथ काम करना चाहिए।" इस कार्यक्रम में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, एनएससी की सीएमडी और अतिरिक्त सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। 1963 में स्थापित, एनएससी, भारत सरकार के अधीन एक मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी, उच्च-गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के कृषि विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है।



## **APEDA ने यूके को जीआई-टैग प्राप्त इंडी और पुलियांकुडी नींबू के पहले निर्यात की सुविधा प्रदान की**

भारत के कृषि निर्यात में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने यूनाइटेड किंगडम को भारत के जीआई-टैग प्राप्त इंडी नींबू और पुलियांकुडी नींबू की पहली हवाई खेप की सुविधा प्रदान की है। विजयपुरा, कर्नाटक से 350 किलोग्राम इंडी नींबू और तेनकासी, तमिलनाडु से 150 किलोग्राम पुलियांकुडी नींबू की पहली खेप, वैश्विक बाजारों में भारत की क्षेत्र-विशिष्ट बागवानी उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव के नेतृत्व में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में कर्नाटक सरकार के बागवानी विभाग, कर्नाटक नींबू बोर्ड और तमिलनाडु के अधिकारियों ने भाग लिया। सहयोगात्मक प्रयास की सराहना करते हुए, देव ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की पहल न केवल भारत की अनूठी कृषि विरासत को बढ़ावा देती है, बल्कि बेहतर मूल्य प्राप्ति और वैश्विक ब्रांडिंग के माध्यम से किसानों को सशक्त भी बनाती है। उन्होंने भारत की समृद्ध क्षेत्रीय विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले जीआई-टैग वाले उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ाने में निर्यातकों और उत्पादकों को समर्थन देने के लिए एपीडा की प्रतिबद्धता दोहराई।

वी. दक्षिणमूर्ति, आईएस, कृषि उत्पादन आयुक्त और कर्नाटक सरकार के सचिव, ने इस निर्यात की सराहना करते हुए इसे राज्य और केंद्रीय एजेंसियों, निर्यातकों और किसान समूहों के बीच मजबूत साझेदारी का प्रमाण बताया। उन्होंने इस उपलब्धि को भारतीय किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने और कर्नाटक की बागवानी क्षमता को बढ़ावा देने की दिशामें एक उल्लेखनीय कदम बताया।



मुख्य रूप से विजयपुरा जिले में उगाया जाने वाला इंडी लाइम अपनी तीखी सुगंध, उच्च रस सामग्री, संतुलित अम्लता और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ-साथ पारंपरिक चिकित्सा और स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं में इसके उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। "तमिऴनाडु के नींबू शहर" - तेनकासी जिले में उगाया जाने वाला पुलियांकुडी लाइम अपने पतले छिलके, उच्च अम्लता, भरपूर विटामिन सी सामग्री और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है, जिसकी कदयम किस्म 55% तक रस देती है। पुलियांकुडी नींबू को अप्रैल 2025 में भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त हुआ, जिससे इसकी विशिष्ट क्षेत्रीय और पोषण संबंधी विशेषताओं को मान्यता मिली। इंडी और पुलियांकुडी नींबू का यह पहला निर्यात न केवल भारत के विविध जीआई पोर्टफोलियो का जश्न मनाता है, बल्कि प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय फल बाजारों में देश की स्थिति को भी मजबूत करता है, जिससे और अधिक क्षेत्र-विशिष्ट कृषि-उत्पादों को वैश्विक मान्यता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है।



**National Seed Association of India**

**909, SURYA KIRAN BUILDING, 19, K.G. MARG, NEW DELHI 110001**

**PH: 011-43533241-43, EMAIL: info@nsai.co.in**

**+91-9311957851**

**Website: www.nsai.co.in**